अमृत वाणी

अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है।

प्रेमचन्द

संपादकीय

नेता प्रतिपक्ष के आरोप गंभीर चिंता का विषय

नगरनिगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने हाल ही में डिमरापाल में खोले गए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था को लेकर हैदराबाद की प्राइवेट संस्था कांन्टिनेंटल के प्रबंधन पर जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर और दुखद है। श्री चौधरी ने इस विषय में कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन भी सौंपा है। अतः इस विषय पर त्वरित एवं समुचित कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है। यह अवश्य है कि किसी भी संस्था में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने वे हर संभव कोशिश करते हैं लेकिन उसके लिए वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी दूसरी संस्था के हित को प्रभावित करें ये न तो नैतिकता मानी जा सकती है और न आदर्श।

जैसा कि बताया गया है कि नगर में बहुप्रतीक्षित सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल खुल तो गया है पर वहां न तो विशेषज्ञ चिकित्सक और न ही तकनीकी चिकित्सा कर्मी समुचित संख्या में उपलब्ध हैं जिससे मरीजों को वहां अपेक्षित सेवा उपलब्ध करना प्रबंधन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। राजेश चौधरी का आरोप है कि संभाग मुख्यालय में संचालित महारानी अस्पताल और मेडीकल कालेज में चिकित्सकों को अधिक लाभ देकर कान्टिनेंटल व्दारा अपनी संस्था में लाने की कोशिश करके शासकीय संस्थाओं की सुविधाओं को आघात पहुंचाकर वहां की इलाज को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बस्तरवासी शासकीय अस्पताल में असुविधाओं को देखते हुए मजबूरी में कन्टीनेंटल में बड़ी राशि व्यय कर इलाज कराने को मजबूर हो जाएं। उन्होंने उल्लेख किया है कि वर्तमान में भी एकमात्र न्यूरो सर्जन को कॉन्टिनेंटल व्दारा अपनी संस्था में रखने के बाद शासकीय अस्पताल न्यूरो सर्जन विहीन हो गया है। अगर यही क्रम चलता रहा तो शासकीय अस्पतालों की चिकित्सा सेवा पूरी तरह चरमरा जायगी।

नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया है कि यदि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शासकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों से ही इलाज करवाना था तो फिर करोड़ों रुपये व्यय कर यह अस्पताल एक प्राइवेट संस्था को देने की जरुरत क्या थी।

श्री चौधरी ने इस मामले में कान्टिनेंटल संस्था व्दारा सुपर स्पेशलिटी संस्था को चलाने के लिए भारत सरकार की ट्रिपल पी योजना के तहत अनुबंध किए जाने की बात कहने पर बस्तरवासियों की जानकारी में यह बात लाने की मांग की है कि उक्त अस्पताल को चलाने के लिए ट्रिपल पी के माध्यम से कितनी रकम खर्च की गई है क्योंकि उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का निर्माण सरकारी भूमि में किए जाने से लेकर निर्माण के सारे खर्च, अस्पताल में लगे सभी उपकरण तक सरकारी है। तात्पर्य यह कि इसमें कॉन्टिनेटल का कोई रकम नही लगा है। इन्हीं वजह से नेता प्रतिपक्ष ने वास्तविकता बस्तरवासियों के समक्ष लाने तथा शासकीय अस्पतालों की सेवा को सुरक्षित रखने की मांग की है।

यहां उल्लेखनीय बात यह है कि वैसे ही बस्तर में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। यहां आसानी से चिकित्सक आना नही चाहते। उस पर अगर जो गिने चुने विशेषज्ञ चिकित्सक एवं तकनीकी चिकित्सा कर्मी हैं, वे भी चले जाएं तो बस्तर के आम लोग अत्यधिक परेशानी के शिकार हो जाएगें। सबके लिए निजी अस्पतालों का व्यय उठाना मुमकिन नही है।अतः इस मामले को गंभीरता से लिए जाने की जरुरत है।

बंगाल का भविष्यः धर्म की लहर या प्रगति की राह

बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वर्ग-संघर्ष, वाम वैचारिकी और सामाजिक न्याय के नारों के इर्द-गिर्द घूमती रही। लगभग तीन दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में रहा। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था। किंतु 2011 में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नई धुरी बनी-तृणमूल बनाम भाजपा। आज स्थिति यह है कि वाम और कांग्रेस हाशिए पर हैं और मुकाबला दो ध्रूवों के बीच सिमट चुका है। यही द्विध्रूवीयता चुनाव को अधिक तीखा और अधिक पहचान-केन्द्रित बना रही है। भाजपा का अभियान चार प्रमुख सूत्रों पर टिका है-बंगाल में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेशी घुसपैठ, महिलाओं की असुरक्षा और भ्रष्टाचार। सीमावर्ती जिलों का उदाहरण देकर यह संदेश गढ़ा जा रहा है कि जनसांख्यिकीय संतुलन बदल रहा है। अवैध घुसपैठ का प्रश्न नया नहीं है, पर उसे इस समय राजनीतिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना, शिक्षक भर्ती घोटाले, हिन्दुओं पर बढ़ते अत्याचार एवं भ्रष्टाचार जैसे प्रसंगों को शासन की विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य स्पष्ट है-70 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं में एक साझा असुरक्षा-बोध निर्मित करना, हिन्दुओं को जागृत करना और उसे मतदान व्यवहार में रूपांतरित करना। आज बंगाल में विकास की सबसे बड़ी बाधा घुसपैठियों का बढ़ना है। घुसपैठियों पर विराम लगाना चाहिए न कि इस मुद्दे पर राजनीति हो।

ममता बनर्जी की चुनौती दोहरी है। एक ओर उन्हें यह संदेश देना है कि वे अल्पसंख्यकों की संरक्षक हैं, दूसरी ओर हिंदू मतदाताओं को यह विश्वास भी दिलाना है कि उनकी आस्था और अस्मिता सुरक्षित है। 2021 के चुनाव में जब भाजपा ने 'जय श्रीराम' के नारे को आक्रामक रूप से उछाला, तब ममता ने 'जय मां दुर्गा' और 'चंडी पाठ' के माध्यम से एक सांस्कृतिक प्रत्युत्तर दिया था। इस बार वे दुर्गा आंगन जैसे

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, पर राजनीतिक रणभेरी बज चुकी है। इस बार संकेत साफहैं- चुनाव विकास बनाम विकास के दावे पर नहीं, बल्कि पहचान, अस्मिता और धर्म की ध्वजा के इर्द-गिर्द घूम सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में प्रस्तावित हिंदू सम्मेलनों को भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक उत्सव भर नहीं, बल्कि चुनावी अवसर में बदलने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी यह समझ लिया है कि यदि चुनाव की जमीन धार्मिक विमर्श पर खिसकती है तो उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोलकाता के न्यू टाउन में 'दुर्गा आंगन' का शिलान्यास और उसे बंगाली अस्मिता से जोड़ने का प्रयास इसी रणनीतिक सजगता का हिस्सा है।

प्रतीकों के जरिए यह संकेत दे रही हैं कि बंगाली हिंदू पहचान भाजपा की बपौती नहीं है। वे धर्म को राष्ट्रवाद की बजाय क्षेत्रीय अस्मिता के साथ जोड़ती हैं-बंगाल अपनी संस्कृति से हिंदू है, पर उसकी राजनीति बहुलतावादी है-यह उनका अंतर्निहित संदेश है। इसी बीच मुर्शिदाबाद में पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर द्वारा 'बाबरी मस्जिद' के शिलान्यास की पहल ने नई जटिलता जोड़ दी है। इससे मुस्लिम मतदाताओं के भीतर एक अलग ध्रूवीकरण की संभावना पैदा हुई है। यदि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, तो तृणमूल का गणित प्रभावित हो सकती है। 2021 में उसे लगभग 48 प्रतिशत वोट और 223 सीटें मिली थीं-जिसमें मुस्लिम मतों का एकमुश्त समर्थन निर्णायक था। भाजपा 38 प्रतिशत वोट के साथ 65 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष बनी। ऐसे में यदि मुस्लिम मत 5-10 प्रतिशत भी इधर-उधर खिसकते हैं, तो कई सीटों का परिणाम बदल सकता है और भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ सकती है।

यहां प्रश्न केवल गणित का नहीं, राजनीति के चरित्र का भी है। क्या बंगाल का चुनाव धार्मिक पहचान के उभार का प्रयोगशाला बनेगा? या यह प्रयोग अंततः विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के प्रश्नों पर लौटेगा? विडंबना यह है कि जिस बंगाल को कभी देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता था-जहां से उद्योग, शिक्षा और सांस्कृतिक नवजागरण की रोशनी फैलती थी, वह आज अधूरे प्रोजेक्ट्स, धीमी औद्योगिक गति और रोजगार के पलायन से जूझ रहा है। कोलकाता की सड़कों पर अधूरी मेट्रो लाइनें और बंद कारखानों की चुप्पी विकास की उस कहानी को बयान करती हैं, जो राजनीतिक नारों के शोर में दब जाती है। 2011 में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट का राज्य से बाहर जाना एक प्रतीकात्मक मोड़ था। भूमि अधिग्रहण के प्रश्न पर जनसमर्थन पाने वाली राजनीति ने उद्योग के प्रति संशय का वातावरण भी बनाया। पंद्रह वर्षों बाद भी बंगाल बड़े निवेश की प्रतीक्षा में है। युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, और कई राज्यों में उन्हें 'बांग्लादेशी' कहकर अपमानित किए जाने की खबरें आती हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न भी है। किंतु चुनावी विमर्श में यह पीड़ा गौण हो जाती है, और केंद्र में आ जाता है-धर्म, पहचान और भय।

ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाती हैं; भाजपा राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का। सी.बी.आई. और ई.डी. की कार्रवाइयों को ममता राजनीतिक प्रतिशोध बताती हैं, जबकि भाजपा उन्हें कानून का पालन। इस टकराव ने प्रशासनिक संवाद को भी राजनीतिक संघर्ष में बदल दिया है। परिणाम यह है कि विकास का एजेंडा आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या धर्म-आधारित ध्रूवीकरण स्थायी राजनीतिक समाधान दे सकता है? इतिहास बताता है कि धार्मिक उभार अल्पकालिक ऊर्जा तो देता है, पर दीर्घकालिक शासन-क्षमता की कसौटी पर उसे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रश्नों से जूझना ही पड़ता है। यदि चुनाव केवल कौन किसका प्रतिनिधि है तक सीमित रह गया, तो कौन क्या करेगा का प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा।बंगाल की आत्मा बहुलतावाद में रही है-रामकृष्ण परमहंस से लेकर रवींद्रनाथ तक, यह भूमि विविध आस्थाओं और विचारों का संगम रही है। यहां दुर्गा पूजा और मुहर्रम दोनों सामाजिक उत्सव का रूप लेते रहे हैं। यदि राजनीति इस सामाजिक ताने-बाने को चुनावी अंकगणित में बदल देगी, तो समाज की संवेदनशीलता पर चोट पहुंचेगी। दूसरी ओर, यदि धार्मिक प्रतीकों का उपयोग सांस्कृतिक आत्मगौरव के साथ विकास-प्रतिबद्धता को जोड़ने में किया जाए, तो वह सकारात्मक भी हो सकता है। इस चुनाव में भाजपा की रणनीति हिंदू मतों का अधिकतम ध्रूवीकरण है; ममता की रणनीति हिंदू पहचान को बंगाली अस्मिता के साथ समाहित कर अल्पसंख्यकों के विश्वास को बनाए रखना है। मुस्लिम दलों की सक्रियता तृणमूल के लिए चुनौती है।

ललित गर्ग

(ये लेखक के अपने विचार है)

डिजिटल इंडिया में महिलाएँ सशक्त या शोषण का शिकार

एक क्लिक में पहचान एक पोस्ट में आवाज़ डिजिटल इंडिया ने महिलाओं को मंच दिया है। लेकिन सवाल यह है यह मंच उन्हें सशक्त बना रहा है या नए तरह के शोषण की ओर धकेल रहा है।

डिजिटल इंडिया को जब भविष्य की तस्वीर के रूप में पेश किया गया था तब उम्मीद थी कि तकनीक समाज की असमानताओं को कम करेगी। महिलाओं के संदर्भ में यह उम्मीद और भी बड़ी थीकृघर की चारदीवारी से बाहर निकले बिना शिक्षा रोजगारए बैंकिंग और अभिव्यक्ति का अवसर। बीते कुछ वर्षों में यह तस्वीर आंशिक रूप से सच भी साबित हुई है। आज भारत में करोड़ों महिलाएँ स्मार्टफ़ोन इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी हैं। वे ऑनलाइन पढ़ रही हैं कमा रही हैं बोल रही हैं। लेकिन इसी डिजिटल स्पेस में एक स्याह सच भी छिपा है जहाँ सशक्तिकरण के साथ.साथ नया शोषण भी जन्म ले रहा है।

आज भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 80 करोड़ से अधिक है जिनमें लगभग 35-40 प्रतिशत महिलाएँ हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे और एनएफ़एस .5 जैसे सर्वे बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की डिजिटल पहुँच तेज़ी से बढ़ी है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभी भी सीमित है। फिर भी स्वयं सहायता समूहों जन.धन खातों यूपीआई और डिजिटल भुगतान ने ग्रामीण महिलाओं को भी धीरे.धीरे डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। बैंक जाने की मजबूरी कम हुई है बिचौलियों पर निर्भरता घटी है और कई महिलाओं ने पहली बार अपने नाम से वित्तीय लेन.देन किया है। यह निस्संदेह सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने महिलाओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दी है। सोशल मीडिया पर वे अपने अनुभव साझा कर रही हैं सामाजिक मुद्दों पर बोल रही हैं और अपने हुनर को दुनिया के सामने रख रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा और स्किलिंग प्लेटफ़ॉर्म ने उन महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं जो किसी कारणवश औपचारिक संस्थानों तक नहीं पहुँच पाईं। ई.कॉमर्स और सोशल मीडिया आधारित छोटे व्यवसायों के ज़रिये हज़ारों महिलाएँ घर बैठे आय अर्जित कर रही हैं। डिजिटल इंडिया की यह तस्वीर उम्मीद जगाती है कि तकनीक महिलाओं के लिए बराबरी का औज़ार बन सकती है। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी है। जैसे.जैसे महिलाएँ ऑनलाइन स्पेस में दिखने लगी हैंए वैसे.वैसे वे नए तरह के उत्पीड़न का शिकार भी हो रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े बताते हैं कि साइबर अपराधों में महिलाओं को निशाना बनाए जाने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऑनलाइन ट्रोलिंग साइबर स्टॉकिंग अश्लील संदेश डीपफेक वीडियो और फ़ोटो मॉर्फ़िंग अब आम समस्या बनती जा रही है। कई मामलों में महिलाओं की निजी तस्वीरों का इस्तेमाल उन्हें डराने बदनाम करने या ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। डिजिटल शोषण की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अदृश्य होता है। पीड़िता घर में बैठी होती है लेकिन हमला उसकी मानसिक शांति पर होता है। कई युवा लड़कियाँ सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने से पहले सौ बार सोचती हैं। कुछ महिलाएँ ऑनलाइन उत्पीड़न के डर से अपनी प्रोफ़ाइल बंद कर देती हैं अपनी आवाज़ दबा देती हैं। यह सशक्तिकरण नहीं, बल्कि एक नई तरह की चुप्पी है जो तकनीक के नाम पर थोपी जा रही है। डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड में भी महिलाएँ तेजी से शिकार बन रही हैं। फर्जी कॉलए डिजिटल अरेस्ट नकली लोन ऐप्स और सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिये महिलाओं को डराकर या भावनात्मक रूप से फँसाकर ठगा जा रहा है। कई मामलों में जीवन भर की बचत मिनटों में साफ़ हो जाती है। खासकर गृहिणियाँ और बुजुर्ग महिलाएँ इस शोषण के प्रति अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि डिजिटल साक्षरता अभी भी सीमित है।

डॉ सुनिधि मिश्रा

(ये लेखक के अपने विचार है)

अजित डोवाल को भी श्रेय

हिसाब से बातचीत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की टीम कर रही थी लेकिन श्रेय 'सबसे ऊपर से', प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है तो उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल को भी श्रेय दिया जा रहा है। गोयल ने समझौते की जानकारी देने के लिए जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठा कर भारत के लिए एक बहुत लाभकारी समझौता कराया है। सोचें, 140 करोड़ लोगों के देश की क्या हैसियत है, जब उसके प्रधानमंत्री को अपनी निजी दोस्ती के सहारे देश का काम कराना पड़ रहा है!

गोयल के इस बयान के एक दिन बाद विदेशी मीडिया समूह ब्लूमबर्ग ने एक खबर दी, जिसे भारत में बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल पिछले साल सितंबर में अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां वे मार्को रूबियो से मिले। बताया गया है कि डोवाल ने रूबियो से कहा कि भारत किसी दबाव में समझौता नहीं करेगा। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक डोवाल ने कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो भारत ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार करेगा। खबर में यह भी बताया गया कि उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। खबर के मुताबिक इससे अमेरिका दबाव में था और डोवाल की बातों ने ट्रंप प्रशासन को मजबूर किया कि वह भारत से समझौता करे। अब चाहे 'सबसे ऊपर के' मोदी की ट्रंप से दोस्ती के कारण हुआ या एनएसए डोवाल के दबाव के कारण हुआ या भारत के 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार की वजह से हुआ लेकिन समझौता हुआ तो उसमें क्या प्रावधान है, क्या शर्तें हैं यह भी किसी को पता नहीं है?

हरिशंकर व्यास

(ये लेखक के अपने विचार है)

वर्ग पहेली 6007

संकेतः बाएं से दाएं
1. भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो प्रमुख शिक्षाविद चिंतक थे (निधन 23 जनू 1953)(8)
6. प्रसिद्ध द्वादश-ज्योतिर्लिंगों में एक मध्यप्रदेश के इस अंचल में स्थित है (3)
7. धीरे-धीरे अपने स्थान से हटना, खिसकना, रेंगना (4)
11. दिनपति, भास्कर, सूर्य, दिनकर (2)
12. बिना पकी भोजन सामग्री (3)
13. सहयोग, मदद (4)
15. शोभा, कांति, छवि (2)
17. पुत्र सहित (3)
19. आमोद-प्रमोद के लिए बनाई गई संस्था (2)
21. दही या छाछ में साग या अन्य खाद्य पदार्थों के छोटे पदार्थों के बारीक टुकड़े मिलाकर बनाया गया खाद्य पदार्थ (3)
23. आराम, सुख, चैन, करार (3)

ऊपर से नीचे
1. ये मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के बेटे थे जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे (7)
2. क्रय-विक्रय की वस्तु, सुस्वादु भोजन (2)
3. विदेश जाकर रहना, परदेश जाना (3)
4. दरवाजा खटखटाने से होने वाली आवाज (3)
5. अपराध, कसूर, भूल (2)
8. अठारह पुराणों में से एक जिसमें सनकादिक ने नारद को संबोधित करके कथा कही है (6)
10. तमगा, मैडल (3)
14. मध्यप्रदेश के अलिराजपुर जिले के तहसील जहां चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली है (3)
18. तीन, तीसरा (2)
20. आहुति के रूप में दिया हुआ, पूर्व समर्पण किय हुआ (2)
22. राजा का मुकुट, छज्जा (2)

वर्ग पहेली 6006 का हल

स्त्री	न	न		छा	या		
प	ल	क	झ	प	क	ते	
		ब	ल			ह	स्त
	स	ज	ना		फ	रा	र
क	मा	नी		सौ	त	न	
र	ज		अ		ह		ह
	प्रे	र	क		ना	म	क
र	मी		रा		मा	म	ला

सुडोकू पहेली क्रमांक- 6007

	4			1				9
	7			6		1		
1	6	3	9					8
	3					2		
	5		7		2		1	
		6					3	
6					5	8	9	2
		5		2			6	
9				8			4	

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक हैं, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी व खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

सुडोकू पहेली क्र. 6006

6	9	5	4	7	3	2	1	8
7	3	4	8	2	1	5	6	9
2	8	1	6	9	5	7	3	4
8	1	2	5	3	9	4	7	6
4	6	7	2	1	8	9	5	3
3	5	9	7	6	4	8	2	1
1	7	3	9	4	2	6	8	5
9	2	8	1	5	6	3	4	7
5	4	6	3	8	7	1	9	2